IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

दोष सिद्धि में लोक अभियोजक की भूमिका:एक आलोचनात्मक अध्ययन

जितेन्द्र कुमार सैनी

Amrit Law College, Dhanauri Roorkee

Abstract : भारत राज्यों का एक संघ है और एक लिखित संविधान द्वारा शासित है जो 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ। भारत में 25 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अपनी औपनिवेशिक विरासत के कारण, भारत एंग्लो-सैक्सन आम कानून न्याय प्रणाली का पालन करता है। संविधान के अनुच्छेद 246 में तीन सूचियों का प्रावधान है जो संविधान की 7वीं अनु सूची में वर्णित हैं। सूची-1 संघ सूची है जो उन विषयों की गणना करती है जिन पर भारत की संसद के पास कानून बनाने की विशेष शक्ति है। सूची-2 राज्य सूची है जो उन विषयों की गणना करती है जिन पर राज्य की विधायिका को कानून बनाने की शक्ति है। तीसरी सूची समवर्ती सूची है, जिसमें उन विषयों की गणना की गई है, जिन पर भारतीय संसद और राज्य के विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर भारतीय संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और किसी राज्य के विधानमंडल के बीच कोई विरोध या असंगतता है, तो केंद्रीय संसद द्वारा अधिनियमित कानून को समाप्त कर दिया जाएगा। अधि भावी प्रभाव। महत्वपूर्ण रूप से, "पब्लिक ऑर्डर" और "पुलिस" को राज्य सूची की क्रमशः प्रविष्टि 1 और 2 में गिना जाता है, जिसका अर्थ है कि पुलिस बल के संगठन, संरचना और विनियम से संबंधित सभी मामले राज्यों के दायरे में आते हैं। हालांकि, 'आपराधिक कानून' और 'आपराधिक प्रक्रिया' को सूची-3, यानी समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। भारतीय संसद और राज्य विधानमंडल दोनों के पास आपराधिक मामलों में अभियोजन पक्ष के आपराधिक न्याय की भूमिका और कार्य में ठोस और प्रक्रियात्मक कानून बनाने की शक्तियाँ हैं। राज्य स्थानीय और विशेष विषयों पर भी कानून बना सकते हैं। इस प्रकार, संवैधानिक योजना के तहत, बुनियादी आपराधिक कानून, यानी, भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम भारतीय संसद द्वारा अधिनियमित किए गए हैं। भारतीय पुलिस अधिनियम भी भारतीय संसद द्वारा अधिनियमित किया गया है। राज्यों ने भी कई स्थानीय और विशेष विषयों पर कानून बनाए हैं। भारत में कुछ राज्यों ने अपने स्वयं के पुलिस अधिनियम भी बनाए हैं। भारतीय पुलिस अधिनियम, 1861, हालांकि, राज्यों में पुलिस बलों के संविधान और संगठन को नियंत्रित करने वाला बुनियादी वैधानिक कानून है। संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी देता है। अनुच्छेद 20 दोहरे जोखिम से सुरक्षा प्रदान करता है। किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अनियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 39- राज्यों को सभी के लिए समान न्याय सुनिश्चित करने का अधिकार देता है। यह निर्धन व्यक्तियों के संबंध में निशुल्क कानूनी सहायता का भी प्रावधान करता है। अनुच्छेद 50 महत्वपूर्ण है क्योंकि यह राज्यों की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्य पालिका से अलग करने का प्रावधान करता हैं।

आपराधिक न्याय प्रणाली में पुलिस, अभियोजन पक्ष, अदालतें और सुधारात्मक प्रशासन शामिल हैं। सिस्टम में इनमें से प्रत्येक घटक को एक दूसरे के साथ सिंक्रनाइज़ेशन में काम करना है। इन अंगों के बीच सामंजस्य ही आपराधिक न्याय प्रणाली की सफलता को संभव बनाएगा। अभियोजन प्रणाली, जिसे व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, को किसी भी बाहरी प्रभाव से स्वतंत्र होकर अपनी भूमिका निभानी होती है। अभियोजक को न्याय मंत्री माना जाता है जिस पर हमेशा निष्पक्षता का भार होता है। यह शोध पत्र आपराधिक न्याय प्रणाली में अभियोजकों की स्थिति, नियुक्तियों और भूमिका पर विश्लेषणात्मक रूप से जोर देगा। यह अभियोजकों की भूमिका की आलोचना और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए उनके सामने आने वाली चुनौतियों पर भी प्रकाश डालेगा। पेपर कुछ मूल्यवान सुझावों के साथ समाप्त होता है, जो सामान्य रूप से आपराधिक न्याय प्रणाली और विशेष रूप से अभियोजन प्रणाली के सुचारू संचालन में योगदान देगा।

कीवर्ड: आपराधिक न्याय प्रणाली, प्रतिकूल प्रणाली, पुलिस, जांच, परीक्षण और समन्वय।

I. INTRODUCTION

एक जटिल सामाजिक-कानूनी समस्या के रूप में अपराध की उत्पत्ति उतनी ही पुरानी है जितनी कि मानव सभ्यता। 1 जब भी पुरुषों और महिलाओं ने खुद को एक संगठित समाज में गठित किया, तो आपराधिक कानून की आवश्यकता महसूस की गई। 2 आपराधिक कानून में मूल और प्रक्रियात्मक कानून दोनों शामिल हैं। मूल आपराधिक कानून एक मामले में पार्टियों के अधिकारों और कर्तव्यों को निर्धारित करता है और प्रक्रियात्मक या विशेषण कानून कानून प्रवर्तन तंत्र को कार्रवाई में सेट करता है। मौजूदा आपराधिक कानून प्रवर्तन मशीनरी में मुख्य रूप से तीन मुख्य घटक शामिल हैं जिनमें पुलिस, अदालतें और सुधारक प्रशासन शामिल हैं। न्यायालय में स्वयं न्यायाधीश, अभियोजक और बचाव पक्ष के वकील होते हैं। इस प्रणाली के सुचारू संचालन के लिए, समाज में कानून के शासन को बनाए रखने के लिए इन सभी घटकों को एक साथ काम करना होगा। पुलिस किसी घटना के दृश्य पर पहुंचने के लिए आपराधिक न्याय प्रणाली की पहली सदस्य होती है, और वे सामग्री का उपयोग करके साक्ष्य एकत्र करती हैं। कानून और उनके पेशेवर कौशल, जिसके बाद कानूनी प्रक्रियाओं के लिए मामले को अदालत में स्थानांतरित कर दिया जाता है। यदि जांच अधिकारी ने कुछ भौतिक साक्ष्यों की उपेक्षा की, तो इस बात की अच्छी संभावना है कि समय के साथ वे गायब हो जाएंगे (प्रगतिशील परिवर्तन),3 जो अभियुक्त व्यक्ति के बरी होने तक के लिए घातक साबित हो सकता है। नतीजतन, एक आपराधिक जांच में जांच अधिकारी का कार्य अभियुक्त के खिलाफ मामले को साबित करने में महत्वपूर्ण है। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 अपराधों को दो व्यापक श्रेणियों में विभाजित करती है: संज्ञेय और गैर-संज्ञेय अपराध। सीआरपीसी की धारा 414 के अनुसार, पुलिस के पास संज्ञेय अपराध की स्थिति में मामले की स्वत: जांच करने और अपराधी पर सफलतापूर्वक मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक साक्ष्य एकत्र करने का अधिकार है। यदि अपराधी अज्ञात है, तो जांच अधिक कठिन हो जाती है, पुलिस को अपने पेशेवर ज्ञान और मुखबिरों की सहायता से अपराधी की पहचान करने और अपराध करने के लिए उसकी प्रेरणा की आवश्यकता होती है। आपराधिक न्याय प्रणाली में अगली महत्वपूर्ण स्थिति आपराधिक न्याय प्रणाली की है अभियोजक। समाज के स्थापित कानूनी नियमों को तोड़ने वालों पर मुकदमा चलाने के लिए हर संगठित समाज में एक अच्छी तरह से विकसित अभियोजन प्रणाली है। हालाँकि, भारत जैसे सामान्य कानून वाले देशों में आपराधिक न्याय प्रणाली नागरिक कानून वाले देशों से भिन्न है। हालाँकि, दोनों प्रणालियों के तहत, यह कार्यालय केंद्र बिंदु है। इसे एक शक्ति केंद्र माना जाता है क्योंकि यह महत्वपूर्ण अधिकार रखता है। यह आपराधिक मुकदमों को शुरू करने और वापस लेने के लिए जनता के अधिकार का भंडार है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 247 और 258 के अनुसार, लोक अभियोजकों, अतिरिक्त लोक अभियोजकों और विशेष लोक अभियोजकों सहित अभियोजकों को उच्च न्यायालयों में मुकदमों और आपराधिक कार्यवाही का संचालन करना है। और मजिस्ट्रेट के न्यायालयों में अभियोजन चलाने के लिए सत्र न्यायालयों और सहायक लोक अभियोजकों की नियुक्ति की जाती है।

अभियोजन की स्वतंत्रता

एक अभियोजक राज्य के हितों की रक्षा करता है, न कि पुलिस की, और यह सुनिश्चित करता है कि अभियोजन निष्पक्ष रूप से संचालित हो। किसी भी आपराधिक मुकदमे का उद्देश्य अपराध की जांच करना और आरोपी के दोष या निर्दोषता का फैसला करना है, और यह अभियोजक की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वह मामले की सच्चाई का निर्धारण करने में अदालत की सहायता करे। नतीजतन, अभियोजक को अपने कर्तव्यों को निष्पक्ष, निडर और जिम्मेदार तरीके से पूरा करने की आवश्यकता होती है। हालांकि, इन अपेक्षाओं को आपराधिक न्याय प्रणाली की वास्तविकताओं के विरुद्ध संतुलित किया जाना चाहिए। 10 अभियोजक को वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए आपराधिक कार्यवाही के प्रत्येक चरण में एक स्वतंत्र भूमिका निभानी चाहिए। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम सुशील कुमार मोदी11 में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस की स्वतंत्र भूमिका के बारे में आर बनाम मेट्रोपॉलिटन पुलिस कमिश्नर13 में लॉर्ड डेनिंग12 के निम्नलिखित शब्दों को उद्धृत किया है: "मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है, हालांकि, कि, भूमि में हर कांस्टेबल की तरह, वह होना चाहिए, और कार्यपालिका से स्वतंत्र है। वह आदेश के अधीन नहीं है यदि राज्य सचिव ... मैं इसे पुलिस आयुक्त का कर्तव्य मानता हूं, जैसा कि देश के कानून को लागू करना प्रत्येक मुख्य कांस्टेबल का काम है। उसे अपने आदमियों को तैनात करने के लिए कदम उठाने चाहिए ताकि अपराधों का पता लगाया जा सके, और वे ईमानदार नागरिक इन मामलों को शांति से कर सकें। उन्हें यह तय करना होगा कि संदिग्ध व्यक्ति हैं या नहीं मुकदमा चलाने के लिए; और, यदि आवश्यक हो, तो मुकदमा लाएँ या देखें कि इसे लाया जाए; लेकिन इन सभी बातों में, किसी के नौकर न बनें, सिवाय कानून के। क्राउन का कोई भी मंत्री उसे यह नहीं कह सकता कि उसे करना चाहिए, या उसे इस स्थान या उस स्थान की निगरानी नहीं रखनी चाहिए, या उसे इस व्यक्ति या उस व्यक्ति पर अभियोग नहीं चलाना चाहिए। न ही कोई पुलिस अधिकारी उसे ऐसा कह सकता है। कानून को लागू करने की जिम्मेदारी उन्हीं पर है। वह अकेले कानून और कानून के प्रति जवाबदेह है।" भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त टिप्पणियों को उद्धृत करने के बाद कहा: "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अनुसार, राय का गठन कि क्या है या नहीं मुकदमे के अभियुक्त को रखने का एक मामला यह है कि जाँच करने वाले पुलिस अधिकारी का है और जाँच में अंतिम कदम केवल पुलिस द्वारा उठाया जाता है और किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा नहीं। यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि वर्तमान की तरह एक कार्यवाही का दायरा और उद्देश्य परमादेश के विशेषाधिकार रिट का सहारा लेकर पुलिस अधिकारी द्वारा अपने कर्तव्य का उचित और ईमानदारी से प्रदर्शन सुनिश्चित करना है।" इस प्रकार, यह अनिवार्य हो जाता है कि पुलिस किसी भी कार्यकारी प्रभाव के बिना कानून लागू करने के लिए। इसी तरह, अभियोजक को भी बिना किसी प्रभाव के अपने कर्तव्य का निर्वहन करने की आवश्यकता होती है। अभियोजक का काम जिसे न्याय मंत्री माना जाता है, न्याय के प्रशासन में राज्य की सहायता करना है । अभियोजक के कार्य की स्वतंत्रता कानून के शासन के केंद्र में है। जैसा कि आर बनाम बैंक्स14 में एवरी जे द्वारा सही ढंग से देखा गया है कि "अभियोजक आपराधिक न्याय प्रणाली में द्वारपाल हैं। यह अब एक अच्छी तरह से व्यवस्थित है नियम है कि अभियोजक पुलिस और अदालतों से स्वतंत्र हैं। जबकि पुलिस, न्यायालयों और अभियोजकों की एक-दूसरे के प्रति जिम्मेदारियां हैं, प्रत्येक के कानूनी कर्तव्य भी हैं जो उन्हें दूसरों से अलग करते हैं। अभियोजक पुलिस जांच को निर्देशित नहीं करता है, न ही वह सलाह देता है पुलिस। सरकार को यह सुनिश्चित

करना चाहिए कि अभियोजक किसी भी कार्यकारी प्रभाव से स्वतंत्र हैं, और बिना किसी हस्तक्षेप के अपने पेशेवर कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकते हैं। बलवंत सिंह बनाम बिहार राज्य17 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि "अभियोजक का यह वैधानिक कर्तव्य है कि वह अपने दिमाग का इस्तेमाल करे और अभियोजन को वापस लेने के बारे में फैसला करे और यह शक्ति गैर-परक्राम्य है और इसे पक्ष में नहीं बदला जा सकता है।" उनमें से जो प्रशासनिक पक्ष में उससे ऊपर हो सकते हैं "। फिर से, सुभाष चंदर बनाम राज्य,18 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि "यह केवल अभियोजक है और कोई अन्य कार्यकारी प्राधिकरण नहीं है जो अभियोजन पक्ष को वापस लेने का निर्णय करता है। अभियोजक द्वारा सहमति तभी दी जाएगी जब इस तरह की वापसी से सार्वजनिक न्याय को व्यापक अर्थों में बढ़ावा दिया जाता है। ऐसा करने में, वह न्यायिक प्रक्रिया के अंग के रूप में कार्य करता है, न कि कार्यपालिका के विस्तार के रूप में। उन्हें पद से हटने के बारे में स्वयं निर्णय लेना होगा, भले ही अप्रसन्नता उनके पद पर बने रहने को प्रभावित कर सकती हो। कोई भी उन्हें मामला वापस लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। अभियोजक न्यायालय का एक अधिकारी है और न्यायालय के प्रति उत्तरदायी है।"

आपराधिक न्याय प्रणाली में अभियोजन की भूमिका

आपराधिक न्याय प्रणाली में अभियोजक की भूमिका का विश्लेषण करने के लिए, क्रिमिनल लॉ रिव्यू (1955) में प्रकाशित क्रिसमस हम्फ्री20 के काम का उल्लेख करना उचित है, जिसे लोक अभियोजकों की नियुक्तियों पर भारतीय विधि आयोग की 197वीं रिपोर्ट (2006) में उद्धृत किया गया है। : "अभियोजक का राज्य, अभियुक्त और न्यायालय के प्रति कर्तव्य है। अभियोजक हर समय न्याय मंत्री होता है, हालांकि शायद ही कभी ऐसा वर्णित किया जाता है। यह अभियोजन पक्ष के वकील का कर्तव्य नहीं है कि वह दोष सिद्ध करे, और न ही किसी को अभियोजक भी केवल सफलता के तथ्य में गर्व या संतुष्टि महसूस करता है। उसे एक अवधि में प्राप्त सजा के प्रतिशत के बारे में और भी कम दावा करना चाहिए। अभियोजक का कर्तव्य या मैं इसे देखता हूं, ट्रिब्यूनल को एक सटीक रूप से तैयार किया गया मामला पेश करना है अभियुक्त व्यक्ति के खिलाफ क्राउन, और इसके समर्थन में सबूत मांगने के लिए। यदि कोई बचाव उसके मामले के साथ असंगत है, तो वह तटस्थतापूर्वक और पूर्ण निष्पक्षता के साथ, तथाकथित सबूतों की जांच करेगा, और फिर जवाब में न्यायाधिकरण को संबोधित करेगा , अगर उसके पास यह सुझाव देने का अधिकार है कि उसका मामला साबित हो गया है। यदि वह अभियुक्त व्यक्ति को दोषी ठहराने में विफल रहता है तो यह उसकी प्रतिष्ठा का खंडन नहीं है। उसका दृष्टिकोण इतना वस्तुपरक होना चाहिए कि जहां तक मानवीय रूप से संभव हो, वह परिणाम के प्रति उदासीन रहे। यह तर्क दिया जा सकता है कि यह अकेले ट्रिब्यूनल के लिए है, चाहे मजिस्ट्रेट या जूरी अपराध या निर्दोषता का फैसला करे। भारत के विधि आयोग ने अपनी 154 वीं रिपोर्ट में बाबू बनाम राज्य के राज्य में दिए गए केरल उच्च न्यायालय के एक बहुत ही स्पष्ट अवलोकन को उद्धृत किया है। केरल22 निम्नलिखित प्रभाव के लिए: अभियोजक न्याय के मंत्री हैं जिनका काम न्याय के प्रशासन में राज्य की सहायता करने के अलावा और कोई नहीं है। वे किसी भी पार्टी के प्रतिनिधि नहीं हैं। उनका काम न्यायालय के समक्ष सभी प्रासंगिक पहलुओं को रखकर न्यायालय की सहायता करना है वे यह देखने के लिए भी नहीं हैं कि अपराधी सजा से बच रहे हैं "अभियोजन आपराधिक न्याय प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण शाखाओं में से एक है, और इसका काम सिस्टम के प्रभावी संचालन के लिए महत्वपूर्ण है। एक अपराधी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए कार्यकारी का कर्तव्य अभियोजन संस्था के माध्यम से किया जाता है। अभियोजक राज्य द्वारा नियुक्त किया जाता है और उसकी ओर से मामलों पर मुकदमा चलाने का प्रभारी होता है। हालांकि यह सुनिश्चित करना अभियोजक का दायित्व है कि मुकदमे का परिणाम दोष सिद्ध हो, उसे परिणाम के साथ अत्यधिक व्यस्त होने की आवश्यकता नहीं है। वह एक न्यायालय द्वारा नियुक्त तटस्थ अधिकारी है, जिससे उम्मीद की जाती है कि वह न्यायालय को एक सच्ची तस्वीर पेश करेगा। यहां तक कि जब वह राज्य का प्रतिनिधित्व करता है, तो यह सुनिश्चित करना भी उसकी जिम्मेदारी है कि आरोपी के साथ गलत व्यवहार न हो। एक कार्यकारी अधिकारी होने के बावजूद, अभियोजक एक अदालत अधिकारी है जो अदालत की मदद करने के लिए बाध्य है। अभियोजक राज्य का प्रतिनिधित्व करता है, जो दूसरे की कीमत पर एक पक्ष के हितों को आगे बढ़ाने के बजाय न्याय के प्रशासन के लिए समर्पित है। उसे ईमानदार और निष्पक्ष होना चाहिए ताकि अभियुक्तों के साथ भी उचित व्यवहार किया जा सके। जब किसी मामले को अभियोजन पक्ष से हटा दिया जाता है, तो अभियोजक का कहना बड़ा होता है। उसे केवल असाधारण परिस्थितियों में ही मुकदमा चलाना चाहिए, ऐसा न हो कि न्याय के प्रशासन में जनता का विश्वास टूट जाए। आपराधिक न्याय प्रणाली में अभियोजक की भूमिका और कार्यों को शिव नंदन पासवान बनाम भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उजागर किया गया है।

प्री-ट्रायल चरण में एक अभियोजक की भूमिका

अभिव्यक्ति परीक्षण को न तो आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1872 में परिभाषित किया गया था और न ही इसे 1882, 1898 और 1973 के बाद के कोडों में परिभाषित किया गया है। इन अभिव्यक्तियों के अर्थ को पुनः प्राप्त करने के लिए शब्दकोश अर्थों का सहारा लेना आवश्यक है। स्ट्राउड्स ज्यूडिशियल डिक्शनरी के अनुसार, विचारण का अर्थ है सक्षम न्यायालय द्वारा किसी भी कानूनी कार्यवाही में विचाराधीन प्रश्न का निष्कर्ष। व्हार्टन लॉ लेक्सिकॉन के अनुसार ट्रायल का अर्थ है किसी मामले की सुनवाई, दीवानी या फौजदारी, किसी न्यायाधीश के समक्ष, जिसके पास अधिकार क्षेत्र है। इस प्रकार, अभिव्यक्ति परीक्षण का कोई सार्वभौमिक अर्थ नहीं है, लेकिन इसे वह अर्थ दिया जाना चाहिए, जो विशेष संदर्भ जिसमें इसका उपयोग किया जाता है, मांग करता है। पूर्व-परीक्षण चरण में, अभियोजक की भूमिका न्यूनतम है। इस चरण के दौरान, पुलिस गिरफ़्तारी करने, तलाशी लेने, इकबालिया बयान रिकॉर्ड करने और गवाहों के बयान दर्ज करने के लिए सक्षम है। हालांकि, एक पुलिस अधिकारी अदालत की पूर्व स्वीकृति के बिना असंज्ञेय अपराध की जांच नहीं कर सकता है। भारत में जांच CrPC, 1973 के अध्याय XII के प्रावधानों के अनुसार की जाती है। जांच पूरी होने के बाद, पुलिस अधिकारी को अदालत में अंतिम पुलिस

रिपोर्ट जमा करनी होती है। पूर्व-परीक्षण चरण में अभियोजक की निम्नलिखित भूमिका होती है: (1) वह अदालत में पेश होता है और आरोपी व्यक्ति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट प्राप्त करता है; (2) वह साक्ष्य एकत्र करने के लिए विशिष्ट परिसर की तलाशी के लिए अदालत से तलाशी वारंट प्राप्त करता है; (3) वह आरोपी व्यक्ति की हिरासत में पूछताछ के लिए पुलिस हिरासत रिमांड प्राप्त करता है (धारा 167); (4) यदि एक आरोपी व्यक्ति का पता नहीं चल पाता है, तो वह उसे घोषित अपराधी घोषित करने के लिए अदालत में कार्यवाही शुरू करता है (धारा 82) और उसके बाद, उसकी चल और अचल संपत्ति (धारा 83) की जब्ती के लिए; और (5) वह अभियोजन की व्यवहार्यता/सलाह के संबंध में पुलिस फाइल में अपनी सलाह दर्ज करता है। यदि जांच पूरी होने के बाद आरोपी व्यक्ति के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला साबित होता है, तो अभियोजक के कार्यालय के माध्यम से अदालत में आरोप पत्र दायर किया जाता है। इस बिंदु पर, प्रथम दृष्टया मामला स्थापित किया गया है या नहीं, इस पर अभियोजक का विचार मांगा गया है। जांच की गुणवत्ता में सुधार के लिए अभियोजक के इनपुट और संक्षिप्त टिप्पणियों को अक्सर ध्यान में रखा जाता है। हालांकि, पुलिस अधिकारियों का अंतिम निर्णय है कि किसी मामले को सुनवाई के लिए लाया जाए या नहीं। यदि जांच अधिकारी (IO) और अभियोजक इस बात पर असहमत हैं कि मामले पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए या नहीं, तो जिला पुलिस अधीक्षक अंतिम निर्णय लेते हैं।

परीक्षण चरण के दौरान एक अभियोजक की भूमिका

परीक्षण चरण के दौरान, अभियोजक सरकार या पुलिस की तुलना में राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक बेजोड़ भूमिका निभाता है। यह न्यायाधीश और अभियोजक की निष्पक्ष भूमिका है जो मुकदमे के भाग्य का फैसला करती है। वास्तविक परीक्षण में, विभिन्न चरण होते हैं और प्रत्येक परीक्षण में अभियोजक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद मामला अभियोजन अधिकारी को सौंप दिया जाता है। यदि प्रथम दृष्टया मामला बनता है तो न्यायालय ने मामले का संज्ञान लेते हुए आरोपी व्यक्ति के खिलाफ आरोप तय किया है। अदालत तब अभियोजन पक्ष के साक्ष्य और अभियुक्तों के बयान दर्ज करने के लिए आगे बढ़ती है। आखिरकार, अदालत दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें सुनती है और निर्णय को सार्वजनिक करती है। मुकदमे के दौरान, अभियोजक के पास दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 321 के अनुसार मुकदमे से मामले को वापस लेने का अधिकार होता है। 30 धारा 321 प्रदान करती है " अभियोजन से वापसी के लिए उन आधारों को इंगित नहीं करता है जिन पर अभियोजक आवेदन कर सकता है या विचार जिस पर अदालत को अपनी सहमति देनी है। पहल अभियोजक की है और अदालत को जो करना है वह केवल अपनी सहमति देना है और न्यायिक रूप से किसी मामले का निर्धारण नहीं करना है। 31 शिव नंदन पासवान बनाम बिहार राज्य में, यह माना गया था कि "न्यायिक कार्य में निहित है सहमति प्रदान करने के लिए न्यायिक विवेक के प्रयोग का सामान्य अर्थ यह होगा कि न्यायालय को स्वयं को संतुष्ट करना होगा कि अभियोजक के कार्यकारी कार्य का अनुचित तरीके से प्रयोग नहीं किया गया है या यह कि यह नाजायज कारणों से न्याय के सामान्य पाठ्यक्रम में हस्तक्षेप करने का प्रयास नहीं है। सुभाष चंदर बनाम राज्य में सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि "धारा 321 के तहत अभियोजन पक्ष की वापसी विशेष रूप से अभियोजक का अधिकार क्षेत्र है। किसी भी कार्यकारी प्राधिकरण के पास अभियोजन वापस लेने की शक्ति नहीं है। लेकिन अभियोजक भी इसे अदालत की सहमति से वापस ले सकता है। धारा 321 के तहत अदालत की सहमति वापस लेने की शर्त के रूप में उस शक्ति के प्रयोग पर रोक के रूप में लगाई जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, सहमति केवल तभी दी जाएगी जब व्यापक अर्थों में सार्वजनिक न्याय को बढ़ावा दिया जाएगा, न कि इस तरह की वापसी से उलट दिया जाएगा। अभियोजक को स्वतंत्र रूप से कार्य करना होगा और न्यायिक रूप से अपना दिमाग लगाना होगा। ऐसा करने में उसे न्यायिक प्रक्रिया के एक अंग के रूप में कार्य करना होगा न कि कार्यपालिका के विस्तार के रूप में। वापस लेने का निर्णय अभियोजक का होना चाहिए, अन्य अधिकारियों का नहीं, यहां तक कि उन लोगों का भी जिनकी नाराजगी से उनकी नौकरी की स्थिति प्रभावित हो सकती है। फिर, राहुल अग्रवाल बनाम राकेश जैन34 में, "अभियोजन वापस लेने की अनुमति इस आधार पर दी गई थी कि मामला लंबे समय से लंबित था और अभियुक्त आदतन अपराधी नहीं था। मामले को अभियुक्तों से पूछताछ के लिए पोस्ट किया गया था और इस बात की कोई जांच नहीं की गई थी कि मामला क्यों लंबित है। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जब अभियोजन पक्ष के साक्ष्य किसी भी समय समाप्त होने वाले थे, तब अभियोजन को वापस लेने की अनुमति देना उचित नहीं है। यह भी कहा गया कि अभियोजन वापस लेने की अनुमति केवल न्याय के हित में और वैध कारणों से दी जा सकती है। इस प्रकार यह एक ऐसे मामले में दिया जा सकता है जो बरी होने की संभावना है और मामले की निरंतरता केवल अभियुक्तों को गंभीर उत्पीड़न का कारण बन रही है, या पार्टियों के बीच सद्भाव लाने के लिए है। पीड़ित पक्षों के उदाहरण पर अभियोजन को वापस लेने की अनुमति देने के विवेक का प्रयोग अभियोजन को रोकने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। यहां तक कि अगर सरकार अभियोजक को अभियोजन वापस लेने का निर्देश देती है, तो भी अदालत को सभी प्रासंगिक परिस्थितियों पर विचार करना चाहिए और यह पता लगाना चाहिए कि क्या वापसी न्याय के कारण को आगे बढ़ाएगी।"

परीक्षण के बाद के चरण में एक अभियोजक की भूमिका

सक्षम अदालत द्वारा परीक्षण और फैसले की घोषणा के पूरा होने के बाद, पीड़ित पक्ष अपीलीय अदालत के समक्ष अपील में जा सकता है। उच्च न्यायालय में अपील करने पर, अभियोजक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 के प्रावधानों के अनुसार, "उच्च न्यायालय द्वारा अपने असाधारण मूल आपराधिक क्षेत्राधिकार में आयोजित मुकदमे में दोषी ठहराया गया कोई भी व्यक्ति उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है और सत्र द्वारा आयोजित मुकदमे में दोषी ठहराया गया कोई भी व्यक्ति न्यायाधीश या एक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश या किसी अन्य न्यायालय द्वारा आयोजित मुकदमे पर जिसमें उसके खिलाफ सात साल से अधिक के कारावास की सजा सुनाई गई है या उसी मुकदमे में दोषी ठहराया गया कोई अन्य व्यक्ति उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है, या यदि कोई हो व्यक्ति मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या सहायक सत्र न्यायाधीश या प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा दोषी ठहराया जाता है या द्वितीय श्रेणी सत्र न्यायालय में अपील कर सकता है। उच्च न्यायालय के अलावा किसी अन्य न्यायालय में आयोजित मुकदमे पर दोषसिद्धि के किसी भी मामले में, अभियोजक को ऊपरी अदालत में इसकी अपर्याप्तता के आधार पर सजा के खिलाफ अपील पेश करने का निर्देश दे सकता है।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 377 प्रदान करती है:

(1) उप-धारा (2) में अन्यथा प्रदान किए गए को छोड़कर, राज्य सरकार उच्च न्यायालय के अलावा किसी अन्य न्यायालय द्वारा आयोजित मुकदमे पर सजा के किसी भी मामले में जनता को निर्देश दे सकती है। अभियोजक अपनी अपर्याप्तता के आधार पर सजा के खिलाफ अपील पेश करने के लिए-ए। सत्र न्यायालय में, यदि दंडादेश मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किया जाता है; और बी। उच्च न्यायालय को, यदि सजा किसी अन्य न्यायालय द्वारा पारित की जाती है "; सी। उप-धारा (3) में, "उच्च न्यायालय" शब्दों के स्थान पर, "सत्र न्यायालय या, जैसा भी मामला हो, उच्च न्यायालय" शब्द रखे जाएंगे। (2) यदि ऐसी सजा किसी मामले में है जिसमें दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम, 1946 (1946 का 25) के तहत गठित दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान द्वारा या इस संहिता के अलावा किसी अन्य केंद्रीय अधिनियम के तहत अपराध की जांच करने के लिए अधिकृत किसी अन्य एजेंसी द्वारा अपराध की जांच की गई है। , केंद्र सरकार लोक अभियोजक को उसकी अपर्याप्तता के आधार पर सजा के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील पेश करने का निर्देश भी दे सकती है। (3) जब सजा की अपर्याप्तता के आधार पर सजा के खिलाफ अपील दायर की जाती है, तो उच्च न्यायालय अभियुक्त को ऐसी वृद्धि के खिलाफ कारण बताने का उचित अवसर देने के बाद ही सजा में वृद्धि नहीं करेगा और कारण बताते हुए, अभियुक्त अपने बरी होने या सजा को कम करने के लिए याचिका दायर कर सकता है। (4) जब अपील दायर की गई हो भारतीय दंड संहिता की धारा 376, धारा 376ए, धारा 376एबी, धारा 376बी, धारा 376सी, धारा 376डी, धारा 376डीए, धारा 376डीबी या धारा 376ई के तहत दी गई सजा, अपील का निपटारा छह महीने की अवधि के भीतर किया जाएगा। ऐसी अपील दायर करने की तारीख। 36 धारा 378. दोषमुक्ति के मामले में अपील के लिए प्रावधान करती है। राज्य सरकार, किसी भी मामले में, उच्च न्यायालय 2 के अलावा किसी अन्य न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति के मूल या अपीलीय आदेश या सत्र न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति के आदेश से उच्च न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने के लिए लोक अभियोजक को निर्देश दे सकती है। पुनरीक्षण में।](2) यदि किसी भी मामले में दोषमुक्ति का ऐसा आदेश पारित किया जाता है जिसमें अपराध की जांच दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का 25) के तहत गठित दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान द्वारा की गई है, या किसी इस संहिता के अलावा किसी अन्य केंद्रीय अधिनियम के तहत किसी अपराध की जांच करने के लिए अधिकृत अन्य एजेंसी, केंद्र सरकार लोक अभियोजक को उप-धारा (3) के प्रावधानों के अधीन उच्च न्यायालय में अपील पेश करने का निर्देश भी दे सकती है। दोषमुक्ति का आदेश। (3) उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के तहत कोई भी अपील उच्च न्यायालय की अनुमति के बिना ग्रहण नहीं की जाएगी। (4) यदि किसी भी मामले में दोषमुक्ति का ऐसा आदेश पारित किया जाता है शिकायत पर और उच्च न्यायालय, शिकायतकर्ता द्वारा इस संबंध में किए गए एक आवेदन पर, बरी होने के आदेश से अपील करने के लिए विशेष अनुमति देता है, शिकायतकर्ता उच्च न्यायालय में ऐसी अपील पेश कर सकता है। (5) उप के तहत कोई आवेदन नहीं - धारा (4) दोषमुक्ति के आदेश से अपील करने के लिए विशेष अनुमति देने के लिए छह महीने की समाप्ति के बाद उच्च न्यायालय द्वारा विचार किया जाएगा, जहां शिकायतकर्ता एक लोक सेवक है, और हर दूसरे मामले में साठ दिन की गणना से दोषमुक्ति के उस आदेश की तारीख। (6) यदि किसी भी मामले में, दोषमुक्ति के आदेश से अपील करने के लिए विशेष अनुमति देने के लिए उप-धारा (4) के तहत आवेदन से इनकार किया जाता है, तो दोषमुक्ति के उस आदेश से कोई अपील नहीं होगी उप-धारा (1) के तहत या उप-धारा (2) के तहत। फिर से सीआरपीसी की धारा 378 में यह प्रावधान है कि जिला मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार, किसी भी मामले में, अभियोजक को वरिष्ठ न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकती है.

आपराधिक न्याय प्रणाली में अभियोजन की भूमिका की आलोचना

आपराधिक न्याय प्रशासन में अभियोजन अधिकारी सरकार के हाथों में प्यादे नहीं हैं. उन्हें निष्पक्ष और निष्पक्ष तरीके से अपनी भूमिका निभाने की आवश्यकता होती है. अभियोजक को सरकार की तुलना में राज्य का प्रतिनिधित्व करना है. वह अपने ग्राहक के कारण के रूप में कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से संभव के रूप में रक्षक होना चाहिए. हालांकि, अपने कर्तव्यों के प्रदर्शन में, आपराधिक न्याय प्रणाली के अन्य पंखों के साथ सिंक्रनाइज़ेशन में काम करना उस पर एक दायित्व है. जब शोधकर्ता ने विभिन्न हितधारकों से संपर्क किया (अनुभवजन्य अध्ययन के लिए उत्तरदाताओं के समूह) पुलिस और अभियोजन के बीच समन्वय के बारे में उनकी राय के लिए, उनमें से अधिकांश अनुमान के हैं, सामान्य रूप से अभियोजन पक्ष के विभिन्न पंखों और विशेष रूप से पुलिस और अभियोजन पक्ष के बीच सहयोग की कमी है.

अभियोजन और जांच में कोई संदेह नहीं है कि आपराधिक न्याय प्रणाली के दो अलग-अलग पहलू हैं. आपराधिक न्याय प्रणाली में पुलिस की भूमिका महत्वपूर्ण है क्योंकि वह पहला है जो घटना के दृश्य तक पहुंचता है और कानून लागू करते समय और उसकी पेशेवर विशेषज्ञता सामग्री एकत्र करती है सबूत जिसके आधार पर मामला कानूनी सुनवाई के लिए अदालत को भेजा जाता है. यदि पुलिस जांच अधिकारी कुछ सबूतों की अनदेखी करता है जो बाद में गायब हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं तो यह हाथ में मामले के लिए घातक साबित हो सकता है. पुलिस और अभियोजन पक्ष में कभी-कभी खोजी मुद्दों पर समन्वय की कमी होती है. उनके कार्य एक-दूसरे से स्वतंत्र हैं क्योंकि जांच कार्य अदालत के बाहर है, जबकि अभियोजक की भूमिका अदालत के अंदर है. यह भी सच है कि वे अन्योन्याश्रित हैं, इसलिए उन्हें न्याय के वितरण में चीजों के सामंजस्य के लिए कार्य करना चाहिए।.37

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) रिपोर्ट के अनुसार, भारत में अपराध, 2018, देश में सजा की दर 50% से कम है% जो संयुक्त राज्य अमेरिका (85%), चीन (99.9%), UK (84.5%), इज़राइल (93%) जैसे देशों की तुलना में बहुत कम है। 99.5% (. देश में कम सजा दर के कारण कई हो सकते हैं, लेकिन भारत में अदालतों द्वारा समय और फिर से प्रकाश डाला गया है कि अभियोजन भी कानून के जनादेश के अनुसार अपनी भूमिका नहीं निभाता है. बेस्ट बेकरी केस 38 में भारत के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई की अदालत के समक्ष आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के विरोध में अभियोजक की भूमिका की आलोचना की है. न्यायालय ने देखा है कि ऐसे व्यक्ति को राज्य के लिए सरकारी वकील के रूप में जारी नहीं रखना चाहिए. फिर से, जयललिता के असम्मानजनक मामले में 39 " जब सरकारी वकील ने कहा, तो उसे दोषियों को सशर्त जमानत देने में कोई आपत्ति नहीं है, न्यायिक प्रणाली की निष्पक्षता और स्वतंत्रता को सवाल में डाल दिया है. न्यायालय ने माना है कि राज्य के कार्यों को करने के लिए राज्य द्वारा सरकारी वकील की नियुक्ति की जाती है. लेकिन जब सरकारी वकील जो हमारी कानूनी प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण शाखाओं में से एक है, तो गलत काम करने वालों की ओर से काम करता है, तो न्यायपालिका की निष्पक्षता और शुद्धता पर सवाल उठता है। "

अभियोजन पक्ष द्वारा अभियोजन पक्ष से वापसी की शक्ति के दुरुपयोग के बारे में, सीआरपीसी की धारा 321 के तहत, शीओ नंदन पासवान बनाम माननीय सुप्रीम कोर्ट. बिहार राज्य और अन्य 40 ने कहा है कि संहिता की धारा 321 " लोक अभियोजक को न्यायालय की सहमति से अभियोजन से हटने में सक्षम बनाती है. इससे पहले कि अभियोजक सेक के तहत एक आवेदन करता है। CrPC के 321, अभियोजक को किसी भी कार्यकारी प्रभाव के अधीन होने के बिना मामले के तथ्यों पर विवेकपूर्ण तरीके से अपना दिमाग लागू करना होगा.

आपराधिक न्याय प्रणाली में अभियोजकों की समस्याएं

हमारे देश में, आपराधिक न्याय प्रणाली इस विचार पर आधारित है कि नागरिकों के खिलाफ किया गया कोई भी अपराध राज्य के खिलाफ अपराध है. राज्य इस आधार पर पीड़ितों की ओर से अपराधियों पर मुकदमा चलाने का भार उठाता है. यद्यपि भारतीय अभियोजक नाममात्र स्वतंत्र हैं, लेकिन उन्हें कई तरह के गैरकानूनी प्रभावों और दबावों के अधीन किया जाता है। 4 भारत में अभियोजकों की समस्याओं को निम्नलिखित प्रमुखों में अभिव्यक्त किया जा सकता है:

I. पुलिस और अभियोजन के बीच समन्वय की कमी

दुनिया के किसी भी हिस्से में न्याय वितरण प्रणाली की सफलता इसके विभिन्न अंगों के बीच समन्वय पर निर्भर करती है. पुलिस और अभियोजन को एक दूसरे से स्वतंत्र काम करना है, लेकिन दोनों को एक दूसरे के पूरक और पूरक होना चाहिए. पुलिस बल जो मामले को दर्ज करने और जांच शुरू करने की शक्तियों के साथ निहित है, वह पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना कर्तव्य नहीं निभाता है.42 किसी भी मामले की जांच का हिस्सा इसकी सफलता निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण है. अनुभवजन्य अध्ययन के दौरान, जब अभियोजन अधिकारियों से उसी के बारे में पूछा गया, उन्होंने टिप्पणी की कि बड़ी संख्या में मामलों में पुलिस द्वारा की गई जांच अपेक्षित स्तर तक नहीं है, जो कि बरी होने के लिए रक्षा काउंसल के लिए एक आसान आधार बन जाता है उनके ग्राहकों की.

II. अतिउत्पीड़न का मुकदमा

अधीनस्थ न्यायालयों में बड़ी संख्या में लंबित परीक्षण हैं. जैसा कि मैडम लाल शर्मा ने ठीक कहा है "देश में अभियोजकों की सही संख्या ज्ञात नहीं है. हालांकि, अनुभव से पता चलता है कि अभियोजन पक्ष मामलों से अधिक प्रभावित हैं और उनकी संख्या उन्हें सौंपे गए मामलों को कुशलता से संभालने के लिए पर्याप्त नहीं है. एक अभियोजक को सौंपे जाने वाले मामलों की संख्या के रूप में एक मानक को ठीक करना मुश्किल है क्योंकि यह मामले की प्रकृति पर निर्भर करेगा. इसके अलावा, एक सरकारी वकील का प्रदर्शन काफी हद तक पीठासीन अधिकारी और अन्य संपार्श्विक कारकों के प्रदर्शन पर निर्भर करता है. जबकि आपराधिक अदालतों की संख्या बढ़ाने के लिए एक मामला है, अभियोजकों की संख्या बढ़ाने के लिए समान रूप से एक मामला है. एक मानक के रूप में, उपयुक्त स्तर के कम से कम दो अभियोजकों को प्रत्येक अदालत के साथ संलग्न किया जाना चाहिए."43 हालांकि, व्यवहार में, स्थिति परेशानी है. फील्डवर्क के दौरान, यह विभिन्न स्टेशनों पर पाया गया है कि एक अभियोजक दो स्थानों पर तैनात है.

III. उचित प्रशिक्षण का अभाव

न्याय वितरण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अभियोजकों को खुले बाजार से भर्ती किया जाता है, और उन्हें बिना किसी संस्थागत प्रशिक्षण के मामलों को सौंपा जाता है. मदन लाल शर्मा देखती हैं "वे अनुभव से सीखते हैं, लेकिन इसमें समय लगता है और इस बीच, मामले पीड़ित होते हैं. यह सुझाव दिया जाता है कि अभियोजकों को उचित प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जाना चाहिए. प्रशिक्षण की अवधि डेढ़ साल हो सकती है. कानून में प्रशिक्षण के लिए छह महीने का समय दिया जा सकता है; एक पुलिस स्टेशन के साथ लगाव के लिए चार महीने; एक सक्षम मजिस्ट्रेट के साथ लगाव के लिए चार महीने; और एक वरिष्ठ और अनुभवी सरकारी वकील के साथ लगाव के लिए शेष चार महीने. प्रस्तावित संस्थागत प्रशिक्षण को समय-समय पर पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों के साथ पूरक किया जा सकता है। ”."44

IV. इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी

अभियोजन अधिकारियों को अनुभवी रक्षा काउंसल का सामना करने के लिए कानून के अच्छे ज्ञान की आवश्यकता होती है. इस तरह के ज्ञान को आत्मसात करने के लिए, अभियोजक के कार्यालय में एक डिजिटल कानूनी डेटाबेस (सहित एक अच्छी तरह से सुसज्जित पुस्तकालय) होना अनिवार्य हो जाता है. इस तरह की कानून की किताबों और ऑनलाइन कानूनी डेटाबेस की कमी अक्सर अभियोजन अधिकारियों के उचित कामकाज में बाधा बन जाती है.

वी. कार्यकारी और राजनीतिक प्रभाव अभियोजक अदालत का अधिकारी होता है जिसका काम न्याय प्रशासन में अदालत की सहायता करना है. वह राज्य का प्रतिनिधित्व करता है न कि पुलिस या सरकार का. उनकी भूमिका किसी भी बाहरी प्रभाव से निष्पक्ष और स्वतंत्र होनी चाहिए. जांच अधिकारियों और अभियोजकों पर बाहरी प्रभाव का झिलमिलाता उदाहरण जैन हवाला केस 45 में देखा जा सकता है. इस मामले में “ नौकरशाह-राजनेता-आपराधिक सांठगांठ ने केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा भ्रष्टाचार के मामलों की जांच और अभियोजन को विफल करने के लिए आवश्यक सभी साधनों का उपयोग किया था. न्यायालय ने इन मामलों की प्रगति की निगरानी की और इसमें शामिल विभिन्न एजेंसियों के कामकाज पर विस्तृत निर्देश दिए और यहां तक कि जांच और अभियोजन के साथ हस्तक्षेप करने से बचने के लिए प्रभारी मंत्री को चेतावनी दी ”.46

V. रिमार्क्स को छोड़कर

समापन टिप्पणी में, एक अभियोजन अधिकारी को अक्सर न्यायिक मंत्री के रूप में दर्शाया जाता है जो आपराधिक न्याय प्रणाली की शुद्धता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है. एक आपराधिक मुकदमे का उद्देश्य हर कीमत पर एक सिद्धांत का समर्थन करना नहीं है, बल्कि अपराध की जांच करना और अभियुक्त की गलती या निर्दोषता स्थापित करना है, और यह अभियोजक का कर्तव्य है कि वह पुलिस या कार्यकारी का प्रतिनिधित्व न करे लेकिन राज्य, और इस कर्तव्य को उसके द्वारा निष्पक्ष और निडरता से और जिम्मेदारी और जवाबदेही की पूरी भावना के साथ छुट्टी दी जानी चाहिए.